www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 5 दिसंबर 2019

दैनिक जागरण

समस्या उतना ही परेशान करेगी जितना उसे स्वयं पर हावी करेंगे

नागरिकता का निर्धारण

केंद्रीय कैबिनेट की ओर से नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही उस पर बहस तेज हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि कई विपक्षी दल पहले से ही उसका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के कारण मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इस विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। नागरिकता संशोधन विधेयक यह कहता है कि पड़ोसी देशों और खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी ही कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता पाने के अधिकारी होंगे। विपक्षी दलों के विरोध का आधार यह है कि आखिर पड़ोसी देशों के मुसलमानों को यह रियायत क्यों नहीं दी जा रही है? इस पर सरकार का तर्क है कि ये तीनों मुस्लिम बहुल देश हैं और यहां मुसलमान नहीं अन्य पंथों के लोग प्रताड़ित होते हैं। इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन इसी के साथ यह सवाल खड़ा होता है कि क्या बाहरी देशों के लोगों को नागरिकता देने के प्रस्तावित नियम भारत की वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव वाली अवधारणा के अनुकूल होंगे? यह सवाल उठाने वाले यह भी रेखांकित करते हैं कि भारत तो वह देश है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनाया। यह बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इसकी अनदेखी कर दी जाए कि असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश से आए करोड़ों लोगों ने किस तरह वहां के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को बदल दिया है?

इसकी अनदेखी नहीं हो सकती कि असम में केवल 19 लाख घुसपैठियों की पहचान हो पाने के कारण राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का विरोध हो रहा है। इस विरोध की वजह यही है कि बाहरी लोगों के कारण स्थानीय संस्कृति के लिए खतरा पैदा हो गया है। क्या इस खतरे को ओझल कर दिया जाए? क्या आज भारत के पास इतने संसाधन हैं कि जो भी बाहर से आए उसे यहां की नागरिकता दे दी जाए? आज तो कोई भी और यहां तक कि कम आबादी और भारत से कहीं अधिक समर्थ देश भी ऐसा नहीं करते। यह सही है कि अगर पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक प्रताड़ित होते हैं तो वे भारत में ही शरण लेना पसंद करते हैं, लेकिन विश्व समुदाय के बीच हमें ऐसे देश के तौर पर भी नहीं दिखना चाहिए जो उपासना पद्धति के आधार पर बाहरी लोगों को शरण देने या न देने का फैसला करता है। बेहतर हो कि पक्ष-विपक्ष ऐसे किसी उपाय वाले नागरिकता संशोधन विधेयक पर सहमत हों जिससे राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ मानवीय मूल्यों की भी रक्षा हो। इस क्रम में उन्हें इसे लेकर सतर्क रहना ही होगा कि उदारता आत्मघात का रूप न लेने पाए।

जरा सोचिए

उन्नीस साल का हो चुका अपना झारखंड चौथे विधानसभा चुनाव के रूप में लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। कायदे से देखा जाए तो यह चुनाव युवावस्था की दहलीज पर खड़े इस राज्य के भविष्य के लिए काफी मायने रखता है। वैसे भी जब घर का बच्चा 19 साल का हो जाता है तो परिवार की चिंता यही होती है कि उसे कैसे सही रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए, ताकि उसका भविष्य सुनहरा हो सके। यही बात झारखंड के साथ भी लागू होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन पहले अपने झारखंड दौरे के दौरान सार्वजनिक सभा में इसे रेखांकित किया था। ऐसे में राज्य के लोगों का यह पावन कर्तव्य है कि वे झारखंड को सही दिशा में ले जाने के लिए मतदान के इस सुअवसर का इस्तेमाल करें। यह काम तभी हो सकता है, जब हर मतदाता यह संकल्प ले कि वह अपने वोट के जरिये झारखंड की किस्मत के निर्धारण में अपनी महती भूमिका निभाएगा। पांच चरणों में हो रहे इस विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दो दिन बाद दूसरे चरण की 20 सीटों पर वोटिंग होगी। इस दिन रिकॉर्ड मतदान कर हमें झारखंड को नई दिशा के लिए आधार तैयार करना है। जितना ज्यादा मत प्रतिशत रहेगा, उतनी अधिक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। उतनी मजबूती से झारखंड में सियासी स्थिरता भी आएगी। झारखंड को इसी राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। अबतक के अपने सफरनामे में इस राज्य को सिर्फ 2014 से ही स्थाई सरकार मिल सकी है। लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को खासतौर से आगे आना होगा। उन्हें न सिर्फ खुद मतदान करना होगा, बल्कि परिवार एवं घर के आसपास से बड़े-बुजुर्गों को भी प्रेरित करते हुए मतदान केंद्रों तक ले जाना होगा। सामाजिक संगठनों को भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने का काम पूरे दायित्वबोध से करना होगा। इसके अलावा प्रशासनिक मशीनरी भी आम मतदाताओं के लिए सहज मतदान कराना सुनिश्चित करे, ताकि लोग पूरे उत्साह के साथ इस महापर्व में अपना योगदान दे सकें।

राज्य के लोगों का यह पावन कर्तव्य है कि वे झारखंड को सही दिशा में ले जाने के लिए मतदान के सुअवसर का इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा मतदान होगा, उतनी ही अधिक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी और उतनी मजबूती से झारखंड में सियासी स्थिरता भी आएगी

आसान नहीं आर्थिक सुस्ती को तोड़ना

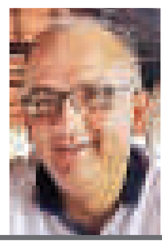

विवेक कौल

चूंकि आर्थिक सुस्ती से बाहर आने का कोई सरल उपाय नहीं बचा इसलिए सरकार का जोर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने पर होना चाहिए

जीडीपी के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि देश में आर्थिक सुस्ती बनी हुई है। जुलाई से सितंबर 2019 की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 4.55 प्रतिशत ही रही। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि आर्थिक विकास का एक पैमाना है। यह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान की सबसे धीमी वृद्धि रही है। वास्तव में यह जनवरी से मार्च 2013 के बाद सबसे धीमी वृद्धि है। इससे पहले की तिमाही, अप्रैल से जून 2019 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.01 प्रतिशत रही थी। सकल घरेलू उत्पाद के चार हिस्से होते हैं-निजी खपत, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात। अगर सकल घरेलू उत्पाद से सरकारी खर्च निकाल दिया जाए तो जो बच जाता है उसे गैर सरकारी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का 87-92 प्रतिशत हिस्सा होता है। यहां यह कहना ठीक होगा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम केवल गैर सरकारी सकल घरेलू उत्पाद को देखें तो इसकी वृद्धि दर जुलाई से सितंबर 2019 की तिमाही में केवल 3.05 प्रतिशत रही। यह वृद्धि पूरे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से करीब 150 आधार अंक कम रही। एक आधार अंक एक प्रतिशत का सौवां हिस्सा होता है।

प्रश्न यह है कि अर्थव्यवस्था के इतने बड़े हिस्से की वृद्धि दर पूरे अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से इतनी अलग क्यों है? अगला प्रश्न यह उठेगा कि गैर सरकारी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर इतनी धीमी क्यों पड़ गई है? यहां यह बताना जरूरी है कि 3.05 प्रतिशत की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद के गैर सरकारी हिस्से की पिछले 15 वर्षों में तीसरी सबसे धीमी वृद्धि रही है। पहली और दूसरी सबसे धीमी वृद्धि अक्टूबर से दिसंबर 2008 और जनवरी से मार्च 2009 के बीच रही थी। पाठकों को याद होगा कि सितंबर 2008 में लीमन ब्रदर्स के दिवालिया हो जाने की वजह से वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत हो गई थी। इसकी वजह से अक्टूबर 2008 से मार्च 2009 के बीच गैर सरकारी अर्थव्यवस्था की हालत काफी डांवाडोल रही थी, लेकिन अभी भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार का कोई संकट नहीं है। इसके बावजूद गैर सरकारी सकल घरेलू उत्पाद, जो कि गैर सरकारी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, काफी दयनीय स्थिति में है। कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, ट्रैक्टर और अन्य कमर्शियल वाहनों की बिक्री इस वर्ष लगातार गिरी है। यह सीधे-सीधे दर्शाता है कि लोगों का अपने आर्थिक भविष्य में विश्वास काफी कमजोर पड़ गया है। इस साल एफएमसीजी कंपनियों की इकाई बिक्री (वॉल्यूम ग्रोथ) में भी गिरावट आई है। लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदने में भी हिचकिचा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में निजी खपत पर काफी मार पड़ी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा निवेश जुलाई से सितंबर 2019 में केवल 1.02 प्रतिशत की दर से बढ़ा। अगर अप्रैल से सितंबर 2019 तक के समय पर नजर डालें तो निवेश 2.54 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। बीते साल इसी अवधि में निवेश 12.55 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। अब अगर निजी खपत और निवेश, दोनों की ही स्थिति खराब है तो अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ रही है? अगर हम केवल सरकारी व्यय को देखें तो जुलाई से सितंबर 2019 की तिमाही में इसमें 15.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह व्यय सामान्य सरकारी व्यय से कहीं ज्यादा था। इस व्यय की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था 4.55 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी, भले ही अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ 3.05 प्रतिशत की दर से बढ़ा। वास्तव में अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान सरकारी व्यय 12.34 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इससे अर्थव्यवस्था को 4.78 प्रतिशत की दर से बढ़ने में मदद मिली है। 2017-18 और 2018-19 में सरकारी व्यय में 14.97 प्रतिशत और 9.25 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली थी। इससे हमें यह मालूम होता है कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी व्यय की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। हालांकि पिछले दो वर्षों में गैर सरकारी सकल घरेलू उत्पाद 6.53 प्रतिशत और 6.32 प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन इस साल जुलाई से सितंबर के बीच यह गिरकर 3.05 प्रतिशत पर आ गया है।

विशेषज्ञ चाहते हैं कि सरकार पहले से ज्यादा पैसे खर्च करे। इस खर्च से कुछ लोगों की आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो वे ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। इससे कुछ और लोगों की आय बढ़ेगी और वे भी ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। इस प्रकार गुणक प्रभाव अपना काम करेगा और आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, लेकिन सरकार पहले से ही काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। केवल इस साल ही सरकारी व्यय में 12.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, 'इन इकोनॉमिक्स, देयर इज नो फ्री लंच।' सरकार का पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने का मतलब है कि सरकार पहले से ज्यादा पैसे उधार भी ले रही है। अगर सरकार पहले से ज्यादा पैसे उधार ले रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोगों के उधार लेने के लिए कम पैसे बच रहे हैं। ऐसे माहौल में ब्याज दरें गिर नहीं रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति लगभग निष्प्रभावी हो चुकी है।

2019 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को 135 आधार अंकों से घटाकर 5.15 प्रतिशत तक लाया है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को लोन देता है। रेपो दर में इतनी गिरावट के बावजूद बैंकों ने अपने कर्ज की ब्याज दरों में कटौती नहीं की है। दिसंबर 2018 में बैंकों की कर्ज देने की औसत दर 10.35 प्रतिशत थी। सितंबर 2019 तक यह 10 आधार अंकों की छलांग लगाते हुए 10.45 प्रतिशत तक पहुंच गई।

अगर सरकार अपना खर्च और बढ़ाएगी तो फिर उसे पहले से ज्यादा कर्ज भी लेना पड़ेगा। इससे बैंकों की ब्याज दरें और बढ़ेंगी। ऐसा होने पर निजी खपत पर और भी मार पड़ेगी। जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है उन्हें पहले से ज्यादा ईएमआई भरनी पड़ेगी। अगर यह हुआ तो इन लोगों की व्यय योग्य आय गिरेगी और फिर निजी खपत और भी कम होगी। निजी खपत भारतीय अर्थव्यवस्था का करीब 56-57 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा जो बहुत सी कंपनियां कर्ज के बोझ तले दबी हैं उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर इन कंपनियों ने कर्ज चुकाना बंद कर दिया तो इसका सीधा असर बैंकों पर पड़ेगा। इस आर्थिक सुस्ती से बाहर आने का कोई सरल उपाय बचा नहीं है। इस समय आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी देशों की तुलना में भारत में भूमि और बिजली, दोनों ही महंगी हैं। हमारे श्रम कानून आर्थिक गतिविधियों के माकूल नहीं हैं। हमारे यहां ब्याज दरें भी बाकी देशों से ज्यादा हैं। इसके अलावा सरकार बहुत सी फालतू चीजों पर पैसे खर्च करती है। न्यायिक और पुलिस सुधारों की सख्त जरूरत है। सरकार को इस जरूरत की पूर्ति करनी चाहिए।

(स्तंभकार इजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक एवं अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

इस्लामी दुनिया और पश्चिमी जगत

तसलीमा नसरीन

पश्चिम को इस्लाम विरोधी बताने वाला कोई मुस्लिम क्या यूरोप-अमेरिका छोड़ पाक या सऊदी अरब में बसना चाहेगा?

तमाम मुसलमानों की ऐसी धारणा है कि इस्लाम की बुराई करने वालों की पश्चिमी देशों में खूब पूछ-परख होती है। ऐसे लोग अपनी खयाली दुनिया में जी रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस्लाम की बुराई करने वालों को दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलता। उलटे अगर किसी ने इस्लाम की खामियों की आलोचना की तो कट्टरपंथी उसके सिर की कीमत लगा देंगे, उसकी जान पर बन आएगी और यूरोप के लोग तो उसका अपमान करेंगे। ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा। हो सकता है कि अकेले कमरे में कुछ नास्तिक उसकी खोज-खबर ले लें। उसे भुलाया भी जा सकता है। पश्चिमी देशों में उनकी कद्र होती है, उनका सम्मान होता है, उन्हें सुफल मिलता है, जो कहते हैं कि इस्लामिक कट्टरवाद खराब है। इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकी जिस इस्लाम की व्याख्या करते हैं वह इस्लाम की गलत व्याख्या है। दरअसल इसी वजह से पश्चिमी देशों में मलाला नायिका है, क्योंकि वह यह कहती फिरती है कि इस्लामिक कट्टरवाद खराब है, इस्लाम नहीं। पश्चिमी देशों में तसलीमा इसलिए जीरो है, क्योंकि वह यह भी कहती है कि इस्लामिक कट्टरवाद को इस्लाम से ही खाद-पानी मिलता है।

पश्चिमी देश उदारवादी मुसलमानों को पसंद करते हैं। इस्लाम के निंदक नास्तिक लोग उन्हें नहीं भाते। उनसे वे जितना हो सके, दूरी बनाकर चलते हैं। उनका मानना है कि इस्लाम में भी परिवर्तन उनके भीतर से आना चाहिए, जैसा कि अन्य धर्मों में हुआ है। उन्हें लगता है कि इस्लाम के बाहर नास्तिकों के चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि इससे नुकसान ही हो सकता है इसलिए हम जैसे नास्तिक को खारिज किया जाता है। हमारे लिए पश्चिम के राजनेता, दार्शनिक, बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री और मानव वैज्ञानिकों और धर्माचार्यों में कोई उत्साह नहीं है, लेकिन कल्पनालोक में रहने वाले मूर्ख जब तक रहेंगे तब तक वे यही कहेंगे कि इस्लाम के खिलाफ लिखने-बोलने वालों को पश्चिमी देशों में इनाम मिलता है। क्या पश्चिमी देशों के पास और कोई काम नहीं, जो वे ऐसे इस्लाम विरोधियों को इनाम दें और अपने लिए मुसीबत मोल लें। सच्चाई यह है कि इस्लाम की स्तुति करने वालों को पूर्व ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी इनाम मिलता है।

अधिकतर मुसलमानों का मानना है कि अमेरिका इस्लाम विरोधी है। वे इसका कारण यह बताते हैं कि अमेरिका इस्लामिक देश अफगानिस्तान और इराक पर बम फेंक रहा है और उसकी चपेट में आने से मुसलमान

मारे जा रहे हैं। उनकी यह भी दलील होती है कि अमेरिका इजरायल को हथियार दे रहा है जो फलस्तीन के मुसलमानों को मार रहा है। यह मानने वालों की भी कमी नहीं कि अमेरिका इस्लाम पर अविश्वास करने वाले अपने यहां के यहूदियों को डॉलर में तौलकर रखता है। जाहिर है कि यह कोरी कल्पना है, लेकिन ऐसी कल्पना करने वालों को समझाए कौन? क्या अमेरिका की किसी सरकार ने आज तक इस्लाम की निंदा की है? क्या वहां की किसी सरकार ने किसी घोषित इस्लाम विरोधी के साथ बैठक की है? कम से कम मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा-सुना। अमेरिकी सरकार तो ऐसे उदारवादी मुसलमानों के साथ ही मुलाकात करती है, जो कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है। अमेरिका के लगभग सभी राष्ट्रपतियों ने बेलाग कहा है कि इस्लाम शांति का धर्म है, बस कुछ भ्रमित लोग अशांति फैला रहे हैं। अमेरिका की किसी भी सरकार ने खुले तौर पर या गोपनीय तरीके से कहीं भी इस्लाम विरोधियों के साथ कोई संपर्क नहीं रखा है। उनमें से कई हैं, जो अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं और इसीलिए अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी उनके संपर्क अच्छे होते हैं।

राजनीतिक शरणार्थियों को बेहतर जीवन देने वाले एक देश में मैंने भी शरण ली थी, लेकिन वहां की सरकार से मुझे एक पैसा नहीं मिला। मैं अपनी किताबों की बिक्री से जो रॉयल्टी मिलती है, उसी से अपना जीवन-यापन करती हूं। आजतक किसी भी देश की सरकार से मुझे फूटी कौड़ी की मदद नहीं मिली। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था ने आगे बढ़कर मेरी मदद भी नहीं करनी चाही इसका कारण यही है कि उन्हें लगता है कि मैं इस्लाम की खामियों की आलोचना करती हूं। दरअसल पश्चिमी देश तब मुझे सिर-आंखों पर बैठाते, जब मैं केवल जेहादियों के खिलाफ लिखती-बोलती। सलमान रुश्दी मशहूर जरूर हैं, लेकिन उन्होंने यह प्रसिद्धि इस्लाम की गलत नीतियों के विरोध में लिखकर नहीं पाई है। अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में जो लोग उनका समर्थन करते हैं, वे भी उनकी रचनाओं में ऐसा बहुत कुछ है, जो पसंद नहीं करते।

पश्चिमी बुद्धिजीवियों में दक्षिणपंथी कम हैं, लेकिन जो हैं उनमें भी मुसलमानों और इस्लाम के प्रति प्रबल सहानुभूति है। यदि यूरोप और अमेरिका इस्लाम विरोधी होते तो वहां इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी कैसे रहती? मुसलमानों को वहां जैसे मानवाधिकार प्राप्त हैं, वैसे अधिकार उन्हें कहीं भी नहीं मिल सकते। इस्लामिक देशों में तो किसी कीमत पर संभव नहीं। आज मुसलमानों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सबसे आगे आने वालों में पश्चिम के बुद्धिजीवी, पश्चिमी लोगों की संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके जैसी सैकड़ों संस्थाएं हैं। जब अवैध घुसपैठ के कानून का शिकंजा कसता है तो मुसलमानों को चर्चों में शरण मिलती है और वहां शरण के बदले ईसाई धर्म स्वीकार करने जैसी कोई शर्त नहीं होती, लेकिन ऐसे ही लोग अपने देश लौटते ही पश्चिम के विरोध में जुट जाते हैं।

पश्चिम के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के लिए भी पश्चिम की पुलिस उन्हें जगह देती है। इतना ही नहीं, उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। मुस्लिमों के लिए पश्चिमी देश किसी स्वर्ग से कम नहीं। विश्वास नहीं होता तो उनसे पूछिए कि उत्तर अमेरिका के किसी अंचल या फिर स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड को छोड़कर क्या वे मिस्र, कतर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, जार्डन या सऊदी अरब में जाकर बसना चाहेंगे? चाहे जितना बड़ा इस्लामपरस्त हो, चाहे जितना इस्लाम विरोधियों को गाली देने वाला हो, शरिया कानून को श्रेष्ठ बताने वाला हो, वह ऐसे किसी देश में नहीं रहना चाहेगा, जहां शरिया कानून हो और इस्लामिक सरकार हो।

(लेखिका प्रख्यात साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता का सूत्र

जीवन स्थितियां प्रतिपल बदलती रहती हैं। हर बार चुनौतियां नए रूप में सामने आ खड़ी होती हैं। जो ढर्रा एक बार सिद्ध हो गया, आवश्यक नहीं कि पुनः फलप्रद होगा। कोई संबंधी, मित्र वर्षों से काम आ रहा है तो हो सकता है इस बार वह काम न आ सके। कोई कार्य निर्विघ्न चलता आ रहा है, किंतु कभी भी अवरुद्ध हो सकता है। इसी तरह कोई लक्ष्य अभेद्य बना हुआ है, पर हो सकता है कि इस बार उसे भेदने में सफलता मिल जाए। जीवन सफलता के लिए जहां बल आवश्यक है वहीं विवेक का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विवेक मनुष्य के बल को उचित दिशा में केंद्रित करता है। किसी परिस्थिति विशेष में कैसे यत्नशील होना है यह निर्णय ही सफलता-असफलता का जनक होता है। भावना के अतिरेक, संवेग, लोभ, क्रोध, मोह में लिया निर्णय मनुष्य की ऊर्जा को स्खलित करने वाला होता है। इससे निकले परिणाम प्रायः पश्चाताप का कारण बनते हैं।

संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सच, स्थाई नहीं है। जीवन पूरी तरह अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जिसे सदैव इसका बोध बना रहता है वह अपने किनारों को कभी टूटने नहीं देता और जीवन की हर परीक्षा के लिए सदैव तैयार रहता है। जब मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार के मोह में नहीं पड़ता, जीवन को उसके सच के साथ जीता है तब उसमें किसी भी स्थिति का सामना करने की शक्ति आ जाती है और वह आगे बढ़ने की राह भी खोज लेता है। यही सबसे बेहतर तरीका भी है।

सफलता-विफलता का अर्थ कुछ होना या न होना नहीं है। परमात्मा ने जो गुण, शक्ति और सामर्थ्य मनुष्य को दी है उसका सदुपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। नेत्र यदि सर्वत्र परमात्मा का रूप देख रहे हैं। रसना यदि परमात्मा का नाम जप रही है। कान यदि परमात्मा की महिमा सुन रहे हैं। हाथ यदि परमात्मा की सेवा में लगे हैं। पैर सद्कर्मों के लिए बढ़ रहे हैं तो तन भी धन्य और मन भी। इसमें पूरे संसार पर राज्य स्थापित कर लेने से अधिक सुख है। यदि यह समझ लिया तो जीवन के सभी दुखों का निदान संभव हो जाएगा।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

मुफ्त डाटा के फेर में उलझते रिश्ते

अंशुमाली रस्तोगी

डिजिटल युग में इंटरनेट और मुफ्त कॉलिंग समय की जरूरत है, पर इतनी भी नहीं कि हर संबंध, हर रिश्ते को बेमानी समझ लिया जाए

खबर है कि मुफ्त इनकमिंग कॉल का दौर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कुछ इस खबर को पढ़ खुश हैं तो कुछ गमजदा! खुश वे हैं, जिनके लिए रिश्ते मोबाइल से अधिक जरूरी हैं। गमजदा वे हैं, जिनकी सुबह मोबाइल से शुरू होकर इसी पर समाप्त होती है, लेकिन उससे भी बड़ी दोषी वे कंपनियां हैं, जिन्होंने प्रत्येक देशवासी को मुफ्त बातचीत की बुरी आदत डाली। जी हां, बुरी आदत! जिसे देखो वह रात-दिन फोन पर चिपका हुआ है। बातें एक बार शुरू होकर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं। घर में हैं तो मोबाइल पर आंखें गड़ाए हैं, बाहर हैं तो मोबाइल कान पर लगा है। गर्दन हमेशा स्क्रीन पर झुकी मिलती है।

ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिनके पास अपनों से बात करने, उनका हाल-चाल लेने के लिए दो मिनट का वक्त नहीं, मगर मोबाइल पर घंटों बातों में व्यस्त रहते हैं। डाटा मुफ्त है और अनलिमिटेड कॉलिंग भी है तो कोई भी बात छोड़ी न जाए, सब कर ली जाए। हम एक ऐसे पागलखाने में तब्दील हो गए हैं, जहां आदमी के हाथों में अखबार या किताबें नहीं, बल्कि मोबाइल नजर आते हैं।

एक जमाना था, जब आदमी सफर अखबार या फिर किताब पढ़ते हुए काटता था, अब तो हर कोई मोबाइल में डूबा हुआ दिखाई देता है। आलम यह है, घर में या पड़ोस में कौन बीमार है, कौन तकलीफ में है यह हमें न मालूम हो, पर कौन-सी कंपनी का मोबाइल अच्छा है और कौन-सी कंपनी कितना डाटा दे रही है यह आज बच्चे-बच्चे को पता होगा। बच्चे भी तो वही कर और सीख रहे हैं, जैसा बड़ों को करता पा रहे हैं। देखा जाए तो फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और भरपूर डाटा समाज के लिए मानसिक रोग बन गए हैं। पहले एक जीबी डाटा पूरे माह देख-भाल कर चलाना होता था, अब दो जीबी डाटा भी पूरे दिन में कम पड़ता है। उसके बाद भी कसर बाकी रह जाती है, इंटरनेट चलाने की। मुफ्त डाटा के चक्कर ने हमें इतना उलझा दिया है कि अब इससे बाहर आ पाना मुश्किल जान पड़ता है, पर असंभव भी नहीं अगर मन में ठान लें तो। सही कहा है, पहले जमाने में सुख भले ही छोटे होते थे, पर भले होते थे। बातें तब भी खूब थीं, पर अनेक रिश्तों के बीच डोर बंधी रहती थीं। बातें जब से बेतार में तब्दील हुईं उनमें और उलझाव आ गए। संबंध सिमट-से गए।

कहा तो यही जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां जबरदस्त घाटे में हैं इसीलिए उन्होंने कॉल दरों में वृद्धि की है। जो भी हो, पर यह कदम देर आयद, दुरुस्त आयद जैसा ही कहा जाएगा। यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। माना कि डिजिटल युग में इंटरनेट और मुफ्त कॉलिंग समय की जरूरत है, पर इतनी भी नहीं कि हर संबंध, हर रिश्ते को बेमानी समझ लिया जाए। डिजिटल समय में हम अपनों के लिए भी वक्त न निकाल सकें। देने वाले चाहे कितने ही तर्क देते रहें महंगे होने वाले डाटा टैरिफ पर, लेकिन अब बात और नेट इस्तेमाल करते वक्त आदमी अब कुछ तो सोचेगा। यह सही है कि इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ना है, पर कुछ तो पड़ेगा। क्यों न कुछ को ही बहुत माना जाए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अखंड भारत का सपना

गुलाम कश्मीर की वापसी का रास्ता शीर्षक से लिखे अपने लेख में कैप्टन आर विक्रम सिंह ने गुलाम कश्मीर के कुछ जिलों को मिलाकर कश्मीर में एक तीसरे केंद्र शासित प्रदेश का जो सुझाव दिया है, वह अखंड भारत के सपने को साकार करने वाला है। निःसंदेह देश की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि 1947 के कबाइली आक्रमण के बाद भारत की केंद्रीय सत्ता द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर के विषय में कभी भी सकारात्मक चिंतन नहीं किया गया। जिसका परिणाम पाक पोषित आतंकवाद के रूप में यह देश पिछले तीन दशकों से भोग रहा है। आतंकवाद की विभीषिका से झुलसती कश्मीर घाटी धीरे-धीरे हिंदू विहीन होती गई। आतंकवादियों के साथ अलगाववादियों की दुरभिसंधि से कश्मीर घाटी की फिजाओं में आजादी का जहर घोला जाने लगा। कश्मीर के इस विषाक्त वातावरण से निकलने वाली भारत विरोध की जहरीली हवा से जब दिल्ली का दम घुटने लगा तो सेना के ऑल आउट ऑपरेशन से कुख्यात आतंकवादियों का सफाया करना जरूरी हो गया। लगातार चलने वाले इस साहसिक सैन्य अभियान से आतंकवादियों की कमर टूट गई। रही-सही कसर भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाक पोषित आतंकवादियों के अड्डों को तहस-नहस करके पूरी कर दी। भारत के मनोबल को बढ़ाने वाली इस सैन्य कार्रवाई का देश के जनमानस पर सकारात्मक असर हुआ और 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार फिर से केंद्र में स्थापित हुई। अपने दूसरे शासनकाल में कश्मीर घाटी की पूर्ण शांति के लिए मोदी सरकार ने जो किया वह अकल्पनीय और अप्रत्याशित था। संविधान के अस्थाई अनुच्छेद-370 एवं 35ए को खत्म कर समूचे जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटना मोदी सरकार का एक साहसिक कदम था। ऐसे में यदि देश का जनमानस पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय भू-भाग को मिलाकर अखंड भारत का सपना संजो रहा है तो इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है।

डॉ. वीपी पांडेय, अलीगढ़

एक बेटी का दर्द

हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या की घटना मानव जाति को शर्मसार करने वाली है। इस घटना को सुनने मात्र से ही रूह कांप उठती है। कैसे इन बेरहम दरिंदों को एक इंसान को जिंदा जलाते हुए जरा भी डर नहीं लगा? आखिर उसका कसूर क्या था? वह तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने घर से निकली थी। रात के अंधेरे में इन दरिंदों ने मदद के नाम पर जो किया वह अक्षम्य ही नहीं, उनके मानव होने पर भी सवाल खड़ा करता है। समाज में ऐसे लोग कैसे हैं। इन्होंने भी किसी मां से जन्म लिया होगा। इनका भी घर परिवार होगा। ये इतने जंगली कैसे हो गए? ऐसी ही घटना कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में भी हुई थी। तब लोगों में उभरे गुस्से को देखते हुए ऐसे मामलों में कुछ कड़े कानून भी बनाए गए, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। उस घटना के बाद न जाने कितनी वारदातें अब तक हो चुकी हैं। देश के हर कोने में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जघन्य वारदात की खबर आ ही जाती हैं। क्या हमारा समाज धर्म संस्कार से शून्य हो गया है? ऐसी घटनाएं समाज को कलंकित करती हैं। सोचिए उस बेटी की क्या तमन्ना रही होगी? किस जज्बे से वह इतना संघर्ष कर अपनी डयूटी निभा रही थी। उसके माता-पिता के सारे अरमान कैसे चकनाचूर हो गए। उन्होंने बड़ी उम्मीद से बिटिया को डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई होगी। वह अभी डॉक्टरी का पेशा ठीक से शुरू भी नहीं कर पाई थी कि दरिंदों की शिकार हो गई। केवल नारेबाजी, शोक सभाएं करने से इसका कोई अंत नहीं होगा। ऐसा करने वालों को इतना कड़ा दंड मिलना चाहिए जिससे उनकी रूह कांप जाए।

ganbansalvw345@gmail.com

सिक्के लेने से इन्कार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई बाजारों में लेनदेन में छोटे सिक्कों को नकारा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी ये सिक्के वैद्य हैं। इन्हें लेने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। किंतु दुकानदार, ऑटो वाले आदि इसे नहीं लेते हैं। पुलिस प्रशासन एवं बैंकिंग संस्थाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक स्पष्टीकरण शासन, प्रशासन, कानूनी संस्थानों और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि संस्थानों द्वारा जारी किया जाना चाहिए। कानूनी सिक्कों को समाज के हर वर्ग को स्वीकार करना चाहिए।

युगल किशोर शर्मा, खाम्बी, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।